

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to formulate a comprehensive policy for water conservation in the country.

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं केंद्र सरकार का ध्यान देश में बढ़ रही पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप-टाउन में चल रही पेयजल की समस्या से हम सभी भली-भांति अवगत हैं। आज वह शहर पीने के पानी के लिए तरस रहा है।

पीने के पानी की समस्या देश में साल दर साल गंभीर होती जा रही है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और जमीन के नीचे के पानी के अंधाधुंध दोहन के साथ ही जल संरक्षण पर कोई कारगर नीति नहीं होने की वजह से देश का भविष्य खतरे में दिख रहा है।

दौसा सहित राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में गर्मियों के आते ही पारा चढ़ने के बाद पीने के पानी की समस्या बढ़ने लगती है। स्वच्छ पीने का पानी आमजन को उपलब्ध करवाना यह सरकार का कर्तव्य है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गंदे पानी को पीने के कारण लोग पेट और संक्रमण की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। एक ओर तो गांवों में साफ पानी नहीं मिलता तो दूसरी ओर, महानगरों में वितरण की कमियों के चलते रोजाना लाखों गैलन साफ पानी बर्बाद हो जाता है। बारिश का अधिकतर पानी बह कर नालियों में चला जाता है।

आखिर पानी की इस लगातार गंभीर होती समस्या की वजह क्या है? नदियों का देश होने के बावजूद ज्यादातर नदियों का पानी पीने लायक और कई जगह नहाने लायक तक क्यूँ नहीं है?

नदियों को साफ करने के लिए शुरू अनेक कार्यक्रम व योजनाएं लाई गई लेकिन आज भी इन नदियों का प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सके हैं। पानी की कमी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में अब तक कोई बड़ी वजह यह है कि सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार कोई ठोस नीति लाये, ऐसा नहीं होने पर निकट भविष्य में पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना होगा।